महोदय, वन भूमि का व्यवस्थापन एक समय सीमा में होना था, लेकिन भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अब तक अनेक राज्यों में भूमि व्यवस्थापन का काम पूरा नहीं हुआ है। यह समिति समूचे राज्य का दौरा कर इस कार्य को संपन्न कराएगी। इस समिति के सचिव, वन सचिव होंगे तथा समिति को समस्त आवश्यक कागजात व सुविधाएं राज्य शासन उपलब्ध कराएगी। इस के खर्च का वहन भारत सरकार करेगी। प्रत्येक 2 महीने में समिति अपनी अपनी कार्य सूचना केन्द्रीय वन मंत्री को देगी। महोदय, वन भूमि व्यवस्थापना आदिवासी राज्यों के जिलों में होना है, जिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडूचेरी व अन्य राज्यों के जिले हैं।

महोदय, वन भूमि पर व्यवस्थापन का कार्य अत्यंत धीमी गति से चलाया जा रहा है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि प्रत्येक राज्य में अब तक भूमि व्यवस्थापन का कार्य कितना शेष है, इस की जानकारी समस्त राज्यों से मंगाए और निर्देश जारी करे कि भूमि व्यवस्थापन में ढील बरतने वाले राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। वन भूमि व्यवस्थापन पूरे तौर पर नहीं होने के कारण आदिवासियों में रोष है।

Demand to give incentives to sugar industry for its revival

SHRI N. R. GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to request the Government to consider the following demands of sugar industry. The sugar industry in our country is facing crisis. There is a steep drop in sugar output to 14.5 million tonnes in 2008-09 season against 26.4 million tonnes in 2007-08. It is due to deficit rains, which it has resulted in a surge in sugar prices in the open market. Many sugar mills are not able to utilize their crushing capacities sufficiently.

The sluggish progress of the South-West monsoon and likelihood of further reduction in sugarcane production may affect profit margins of sugar mills in the next season. Hence the sugar industry deserves incentives from the Government. The sugar industry should be allowed duty free import of sugarcane harvesting equipment. To purchase sugarcane harvesters, 3.5 per cent subsidy should be given to the Farmers' Cooperative Societies and also soft loan for the balance amount. The industry is asking for permanent withdrawal of tax on self-generated electricity to encourage captive power generation. The Government should provide special facilities for letters of credit to sugar factories to enable them to import raw sugar to tide over the shortage of domestic sugar production.

The excise duty on rnolasses should be rationalized to Rs. 250 per tonne which is not at Rs. 750 per tonne. Tax Holiday for the revenue earned from co-generated power should be extended for another ten years and thus will encourage more investment in this sector. "Declared goods" status should be granted to ethanol.

Therefore, I urge upon the Government to pass necessary orders in this regard.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand to increase number of seats in various medical colleges in Bihar

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार) : उपसभापति महोदय, 2008-09 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश की बढ़ती हुई आवश्यकता और वित्तीय संसाधन को देखते हुए यह सुझाया गया है कि हमारे पास जो भी पुराने संसाधन और

7.00 P.M.

आधारभूत संरचनाएं हैं, उनका समुचित दोहन किया जाए। इसी सुझाव के तहत मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि वह पटना में 80 एकड़ में फैले और स्वयं के निर्मित भवन में कई वर्षों से चल रहे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.एम.एस.) में 100 छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति प्रदान करे। साथ ही, बिहार के अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों, यथा पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज आदि में प्रत्येक में 50-50 सीटें बढ़ाई जाए, जिससे बिहार के छात्रों को इस प्रयोजनार्थ अन्यत्र न भटकना पड़े और इस देश में चिकित्सकों की जो कमी है, उसकी भी भरपाई हो सके। सदन में प्रतिपक्ष के नेता भी अरुण जेटली ने भी स्वास्थ्य परिचर्चा में भाग लेते हुए इस आशय का वक्तव्य दिया था।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

Demand to stop supply of ready to use therapeutic foods in the country

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I would like to draw your attention to the recent information that international agencies like UNICEF have been importing some kind of branded 'Ready to Use Therapeutic Foods' for the treatment of severely malnourished children and this has been used and distributed without the permission of the Government of India. This is highly objectionable.

International agencies and vested interests are attempting to push these foods in contravention of the Government policy. I believe that indiscriminate distribution of such foods will commercialize young child feeding through market driven approaches. This would change the feeding patterns of young children in the villages and simplify the management of malnutrition. This will also destroy local solutions developed by the people; even the Indian Academy of Pediatrics recommends a modified family pot approach for this.

The Government of India's letter no. Z-28020/50/2003-CH, Ministry of Health and Family Welfare stated as follows:

"The Ready to Use Therapeutic Foods is plum peanut, from France @ US $ 60 per child. RUTFs are not an accepted strategy of the Government of India, neither under RCH nor ICDS."

I am astonished how this food were procured and distributed by UNICEF in some of the States without any knowledge or approval of the Ministry of Women and Child Development, Government of India.

I demand that this RUTF procurement and supply should immediately be stopped.

Demand to take steps to facilitate early construction of Dadri Power Project in Uttar Pradesh

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरा Special Mention UP में power crises और shortage से मुताल्लिक है।

सर, 21 जुलाई को हिन्दुस्तान टाइम्स में इश्तिहार के ज़रिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सारे पावर प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दिया है। इस पत्र में दादरी पावर प्रोजेक्ट का नाम-ओ-निशां नहीं है। 2003 में सरकार ने 2500 एकड़ किसानों की उपजाऊ ज़मीन उनसे हासिल करके कम्पनी को उपलब्ध करा दी थी। आज 2009 में यह प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर ही है। किसानों का बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था और वे जेल भी